They are lodged with the Ad-Hoc Claims Commissioner/Ex. Officio Claims Commissioner, as the case may be. There are 220 claims cases under the Indian Railways Act 1890 pending finalisation with Ad-Hoc Claim Commissioners/Ex-Officio. Claims Commissioners for more than 4 months.

कोरबा तथा अन्य स्थानों पर छोटी लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलना

2741. **श्री छविराम अर्ग** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोरबा, रांची, पले राजधरा, बैलाडीला एवं सवाई माधोपुर, श्यापुर, मुरैना, ग्वालियर, भिंड आदि होते हुए रेल लाइनों को बड़ी रेल लाइनों में बदलने का प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार को प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा क्या उस जद्देश्य के लिए इस बीच सर्वेक्षण किया गया है अथवा किया जा रहा है; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार इस बात को ध्यान में रखते हुए, कि मध्य प्रदेश में एक पिछड़ा राज्य है, इन रेलवे लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलने के कार्य प्राथमिकता देने के प्रश्न पर गंभीरता से विचार करेगी ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). निम्नलिखित रेलवे लाइनों के लिए सर्वेक्षण किये गये हैं :

(1) रांची-लोहारडागा–छोटी लाइन से बड़ी लाइन में आमान परिवर्तन ।

(2) रायपुर–धमतरी

निम्नलिखित छोटी लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलने के लिए अभी तक कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है :—

1. ग्वालियर से शिवपुरी
2. ग्वालियर से भिण्ड
3. ग्वालियर से शिवपुरकलां

देश के पिछड़े इलाकों में नई रेलवे लाइन के निर्माण और आमान परिवर्तन की जरूरतों से सरकार अवगत है परन्तु इस समय संसाधनों की अत्याधिक तंगी के कारण इन परियोजनाओं पर विचार करने के लिए बेहतर समय की प्रतीक्षा करनी होगी ।

Parcel Handling work at Allahabad

2742. SHRI ISHWAR CHAUDHRY: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) when there was no stipulation in the Agreement for supply of 110 men daily for performing parcel handling work at Allahabad then why records were maintained by Railway staff for supply of labour by the Society;

(b) whether it is a fact that it was within the knowledge of the Society that they are paid lumpsum payment of Rs. 21,175/- per month on the basis of employment of 110 men daily and they therefore got the fictitious records maintained by Railway Staff by bribing them;

(c) whether it has been brought to the notice of the Government that the Society was/is employing not more than 60 to 70 labourers per day but in order to syphon off the surplus money is showing attendance in fictitious names; and

(d) if so, whether any enquiry has been conducted together with details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN): (a) The Society,